दैनिक पायनियर पेज न 06

आर्थिक महायज्ञ में जुटा एक योगी

राज बहादुर सिंह
(लेखक पायनियर हिन्दी लखनऊ के ब्यूरो चीफ हैं)

योगी आदित्यनाथ की छवि एक राजनीतिक पुंज की मानी जाती रही और पांच साल सरकार चलाकर फिर दो तिहाई बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन होकर गोरख पीठाधीश्वर ने इस पर मुहर भी लगाई लेकिन हालिया मुंबई प्रवास ने उनकी छवि में कुछ और जोड़ दिया है। अब आदित्यनाथ एक ऐसे योगी बन गए हैं जिन्हें 'राजनीति' से ज्यादा अब 'अर्थनीति' की फिक्र है। यह योगी की छवि का एक स्वागत योग्य विस्तार है।

दिल्ली यानि भारत की सत्ता का रास्ता अगर लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है वैसे ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का मार्ग देश के सबसे बड़े राज्य (आबादी की दृष्टि से) से होकर ही गुजरेगा और भाजपा के नेतृत्वकाली देश व प्रदेश की सरकारों ने इसे समय रहते न केवल समझ लिया है बल्कि इस दिशा पर अमल भी शुरू कर दिया है। इसकी झलक पिछले दिनों विदेशी भूमि पर देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनकी काबीना के कई मंत्री (उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक सहित) व अधिकारी विदेश भ्रमण पर गए थे। न केवल मंत्री वरन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भी इस मिशन में लगाया गया। अमेरिका व यूरोपीय देशों की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां के उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें सूबे में उद्योग धंधों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें इस बात के प्रति आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश की छवि जिन कारणों से उद्योग जगत के लिए प्रतिकूल थी वह अब बीते जमाने की बातें हैं और अब यूपी नए विकासोन्मुखी कलेवर के साथ औद्योगिक जगत का स्वागत करने को तैयार है।

सीएम योगी ने फिल्म जगत के लोगों से उत्तर प्रदेश में शूटिंग सहित अन्य फिल्मी गतिविधियों को बढ़ाने का आह्वान किया और खासकर उन्हें नोएडा की फिल्म सिटी को गुलजार करने को कहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव का भी ऐलान किया। योगी की इस पहल ने भाजपा विरोधियों को विचलित भी किया और पहली व त्वरित प्रतिक्रिया शिवसेना की ओर से आई। शिवसेना के बड़बोले प्रवक्ता संजय राउत ने बिलबिलाते हुए कहा कि क्या अमिताभ बच्चन व माधुरी दीक्षित जैसी फिल्मी हस्तियां मुंबई छोड़ कर नोएडा में जाकर रहने लगेंगी? क्या मुंबई से फिल्म निर्माण में शीर्ष होने का तमगा कोई और शहर ले लेगा? संजय राउत की प्रतिक्रिया में उनकी असुरक्षा साफ नजर आती है। उन्हें शायद

यह भान नहीं रहा कि जीवन हो संसार। यह परिवर्तनशील है। क्या यह सच नहीं है कि मुंबई से पहले कोलकाता हिंदी फिल्मों के निर्माण का भी मुख्य केंद्र था लेकिन देखते देखते हालात बदलते गए और कोलकाता हिंदी फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र से हटता गया और इसका स्थान मुंबई लेता गया और विगत 70-80 सालों में मुंबई का फिल्मी सफर कैसे आगे बढ़ा यह अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा यह अनिश्चित है और इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और मंत्रियों व अधिकारियों का विदेश भ्रमण व सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई प्रवास तीन दिवसीय मेगा इवेंट को सफल बनाने की कवायद का पूर्वाभ्यास ही है। योगी ने मुंबई प्रवास के दौरान न केवल उद्योग जगत के शीर्ष लोगों से मुलाकात की वरन फिल्मी हस्तियों से भी संवाद किया। सीएम ने विभिन्न उद्योगपतियों से अलग अलग भी मुलाकात की और उनसे विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। उद्योगपतियों के इस जमावड़े में अंबानी, अडाणी,बिड़ला सहित अन्य दिग्गज उद्योग घरानों के शीर्ष कर्ता धर्ता शामिल थे।

लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुंबई प्रवास ने केवल शिवसेना को विचलित किया हो, ऐसा नहीं है। शिवसेना के साथ गलबहियां करने वाली कांग्रेस की बदहवासी भी उभर कर सामने आ गयी। कांग्रेस के पूर्व राज्य सभा सदस्य हुसैन दलवई ने योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर अनावश्यक, अवांछित, अनर्गल टिप्पणी करते हुए भगवा कपड़े व हिंदुत्व पर अपनी कुंठा प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे वस्त्र पहनने व धर्म से उद्योग नहीं आता और उसके लिए मॉडर्न होना पड़ता है। जाहिर है कि दलवई का बयान कुछ और नहीं बल्कि उनकी सियासी जिहालत ही है जिसे खुद कांग्रेस को आगे आकर खारिज करना चाहिए लेकिन शायद कांग्रेस अब उस दौर से आगे निकल चुकी है जब वह राजनीतिक शिष्टाचार में विश्वास करती थी। ऐसे में उससे यह अपेक्षा करना कि वह अपने पूर्व राज्यसभा सदस्य के बयान की निंदा करेगी केवल दिवा स्वप्न ही हो सकता है।

उत्तर प्रदेश को आर्थिक व औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाने का सीएम योगी का लक्ष्य और इसके लिए किए जाने वाला परिश्रम उन्हें अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से अलग दिखाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पांच साल सत्ता संचालन का अवसर मिला था लेकिन उन्होंने इस दौरान प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिसका उल्लेख किया जा सके। उनका सारा ध्यान लैपटॉप व टैबलेट बांट कर अगला चुनाव जीतने पर ही केंद्रित रहा लेकिन अगला क्या वह लगातार दो विधानसभा व दो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अखिलेश से पहले मायावती ने पांच साल बहुमत की सरकार चलाई लेकिन उनसे यह आशा करना ही फिजूल था कि वह प्रदेश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कारगर कोशिश करेंगी। उनके लिए आर्थिक सुदृढ़ीकरण का क्या मतलब था यह किसी से छिपा नहीं है।

किसी राज्य के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के प्रयास कोई चंद हफ्तों में फलीभूत नहीं होते। इसमें वक्त लगता है वह भी जब सभी प्रोजेक्ट्स की सतत व सघन मॉनिटरिंग की जाए। और योगी सरकार से यही आशा की जानी चाहिए कि देश-विदेश से निवेश संबंधी जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं उनका क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी व कर्मठता से किया जाए। यह कोई आसान लक्ष्य नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व को इस संबंध में नौकरशाही का पूरा सहयोग भी चाहिए। जिस समर्पण की अपेक्षा राजनीतिक नेतृत्व से होती है वैसी ही अपेक्षा अफसरशाही से भी होगी तभी वांछित परिणाम मिल सकेंगे। आम जनमानस को उम्मीद है कि जिस मेहनत व समर्पण के साथ योगी प्रदेश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं वह यथाशीघ्र धरातल पर फलीभूत होगा।